बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 06 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 10 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

विकास की नई राह! गडकरी बोले- 2027 तक ठोस कचरे से होगा सड़क निर्माण, बदलेगा भारत

नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 2027 के अंत तक भारत में सभी ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाएगा। गुरुवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के 120वें वार्षिक सत्र में बोलते हुए, गडकरी ने बताया कि 80 लाख टन कचरे को पहले ही अलग करके सड़क निर्माण परियोजनाओं में उपयोग के लिए निर्धारित किया जा चुका है। गडकरी ने कहा कि कोई भी सामग्री बेकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति बेकार है। सही तकनीक और नेतृत्व के साथ, हम कचरे को धन में बदल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2027 तक, हमारी योजना सभी ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण के लिए करने की है।

केवल कहानी गढ़ने पर ध्यान, एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कही बड़ी बात

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुनवाई के दौरान, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एक बड़ा आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और एजेंसियां चुनाव निकाय के चल रहे प्रयासों में सहयोग करने के बजाय जनता की धारणा को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सीधे-सीधे आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के वकील ने याचिकाकर्ताओं के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें एक व्यक्ति का दावा है कि उसे ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी का कहना है कि दिए गए पतों पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद भी है। अधिवक्ता द्विवेदी का तर्क है कि याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन अदालत में हलफनामा दाखिल करने से पहले अपने दावों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का कहना है कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं की संख्या में सबसे बड़ी कमी आई है, जो 47 लाख है। हालाँकि सितंबर 2025 तक बिहार में वयस्क जनसंख्या का आधिकारिक अनुमान 8.22 करोड़ है (जिनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए थे), अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। इस प्रकार, 80 लाख यानी बिहार की कुल वयस्क जनसंख्या का लगभग 10त्न मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह गए हैं। वयस्क जनसंख्या और मतदाताओं के अनुपात में इतनी तीव्र गिरावट भारत और बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है। देश के किसी भी राज्य में इससे पहले 10त्न से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा। 7 अक्टूबर, 2025 को कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन 3.66 लाख मतदाताओं का विवरण मांगा, जो मसौदा मतदाता सूची का हिस्सा थे, लेकिन बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची से बाहर हो गए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भ्रम की स्थिति है।

26/11 के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई सोनिया गांधी ने रोकी? पूनावाला का गंभीर आरोप, जवाब माँगा

नई दिल्ली । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आज राजधानी स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ उन्होंने 26/11 के हमलों के संबंध में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किए। उन्होंने कहा कि हमले के समय, जब गृह मंत्री, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और अन्य मंत्री पाकिस्तान पर जवाबी हमले के पक्ष में थे, क्या सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित किया कि भारत 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब न दे? क्या यह उनकी वोट बैंक की राजनीति थी जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया? पूनावाला ने आगे ज़ोर देकर कहा कि गांधी-वाड्रा परिवार को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। पूनावाला ने याद दिलाया कि राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत के जवाबी हमले में गिरे भारतीय विमानों की संख्या जानने के लिए ज्यादा उत्सुक थे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों को पूरी आजादी दी थी। उन्होंने पूछा, आखिर गांधी-वाड्रा परिवार 26/11 से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता पर सवाल क्यों उठाता रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की ए टीम है और उसके प्रति नरम रुख रखती है। उन्होंने आगे दावा किया कि सोनिया गांधी और गांधी-वाड्रा परिवार इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि गांधी-वाड्रा परिवार को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।

पूनावाला ने याद दिलाया कि राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत के जवाबी हमले में गिरे भारतीय विमानों की संख्या जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक थे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों को पूरी आज़ादी दी थी। उन्होंने पूछा, आखिर गांधी-वाड्रा परिवार 26/11 से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता पर सवाल क्यों उठाता रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की ए टीम है और उसके प्रति नरम रुख रखती है। उन्होंने आगे दावा किया कि सोनिया गांधी और गांधी-वाड्रा परिवार इसके लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार हैं।

वक्फ संपत्ति पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका को मंजूरी, केंद्र ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने पर विचार के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले वक्फ-बाय-यूजर प्रावधान को लेकर पहले भी कोर्ट ने अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को सभी वक्फ संपत्तियों, जिसमें वक्फ-बाय-यूजर भी शामिल है, की अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। इससे पहले 15 सितंबर को कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ मुख्य धाराओं पर अस्थाई रोक लगा दी थी। इनमें यह शर्त शामिल थी कि केवल वे ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हों। हालांकि कोर्ट ने पूरी अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार किया था और इसे संवैधानिक माना था। मामले में अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का वक्फ-बाय-यूजर प्रावधान हटाने का फैसला गैर-तर्कसंगत नहीं है और यह धारणा कि इससे वक्फ जमीन सरकार द्वारा कब्जा ली जाएगी, गलत है। बता दें कि वक्फ-बाय-यूजर का मतलब है कि यदि किसी संपत्ति का लंबे समय तक बिना रुके धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए उपयोग हो रहा है, तो उसे वक्फ माना जाएगा, चाहे उसका औपचारिक दस्तावेज न हो। वहीं इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी के वकील नजम पासा ने बताया कि संशोधित कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया गया था, जिसमें से पांच महीने गुजर चुके हैं और अब केवल एक महीना बचा है, इसलिए समय सीमा बढ़ानी जरूरी है। दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका की सूचीबद्धता पर आपत्ति जताई और कहा कि केंद्र को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इसपर मुख्य न्यायाधीश बीआर गावई ने कहा कि सूचीबद्ध करना राहत देने जैसा नहीं है, बस सुनवाई के लिए जगह देना है। गौरतलब है कि केंद्र ने बीते छह जून को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके तहत देश भर की सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का डिजिटल और भौगोलिक टैगिंग के साथ रिकॉर्ड बनाना अनिवार्य है। इसके लिए छह महीने का समय तय किया गया है। विस्तार से जिक्र है. इस घटना के अगले दिन 14 दिसंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी.

शराब घोटाले का खुलासा : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ईओडब्ल्यू को दिया अल्टीमेटम, कहा- दिसंबर तक जांच पूरी कर दें फाइनल रिपोर्ट

नई दिल्ली । छत्तीसगढ़ में हुए भारी शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने और फाइनल रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि डिसंबर के आखिरी सप्ताह तक फाइनल रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सितंबर के आखिरी सप्ताह में अपलोड किए गए ऑर्डर में दिया। इसके बाद ED और EOW ने जांच को तेज गति से आगे बढ़ाया है। ED आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों के बयान दर्ज करने में जुटी है, जिनमें 7 रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। ED के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि 'इस केस की जांच लगभग 2 साल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए समय में हम फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे।' इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले से संबंधित 13 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में छत्तीसगढ़ और यूपी में दर्ज FIR, ED की ECIR और जमानत याचिकाएं शामिल थीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच पूरी होने के बाद ही याचिकाकर्ता नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। EOW की जांच में पता चला है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाला किया गया। अनवर ढेबर को 90 करोड़ से अधिक मिले, जिन्हें उसने रिश्तेदारों और CA के नाम पर कंपनियों में निवेश किया। चालान के अनुसार, शराब डिस्टलर्स से कमीशन और बी पार्ट की बिक्री से मिलने वाले पैसे का 15त्न अनवर ढेबर को जाता था, जो अपने सहयोगियों विकास अग्रवाल और सुब्बू के जरिए लेता था। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, अन्य अधिकारी और कारोबारी जैसे अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी, दिलीप टुटेजा, सुनील दत्त गिरफ्तार हैं। श्वष्ठ और श्वहड्ड के अनुसार, विदेशी शराब पर सिंडिकेट द्वारा लिए गए कमीशन का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक

नई दिल्ली । दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव किया है. स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से लगभग एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव किया गया है.

ये बदलाव 30 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर साल दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के समय सबसे यादा भीड़ देखी जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए इस बार रेलवे ने ये एहतिहाती कदम उठाए हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने और अव्यवस्था रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13, 14 और 15 से एक ही समय पर कई भीड़भाड़ वाली गाड़ियां रवाना होती थीं, जिससे यात्रियों और रेलकर्मियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. विशेष रूप से 12-13 और 14-15 एक ही प्लेटफॉर्म के दोनों ओर स्थित हैं, जिससे भीड़ का दबाव एक साथ बढ़ जाता था. इसे कम करने के लिए प्लेटफॉर्म बदलाव किया गया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य जांच लें. अधिकारी ने बताया कि, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अस्थायी बदलाव किया गया है, इससे यात्रियों को त्योहारों के दौरान बेहतर अनुभव मिलेगा. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये परिवर्तन अस्थायी हैं और 30 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे.

यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट, स्टेशन घोषणाओं या सूचना पट पर अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म अवश्य जांच लें ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े. वहीं, त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक और अस्थायी व्यवस्था के तहत दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों - नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और गाजियाबाद जंक्शन पर 15 से 28 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी.

रेलवे ने बताया कि यह निर्णय भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लिया गया है. हालांकि, यदि किसी बुजुर्ग या महिला यात्री को स्टेशन तक छोड़ने की आवश्यकता हो, तो ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को विशेष अनुमति के तहत प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, ऑनलाइन ऐप्स पर भी प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है.

मोहन भागवत : विरासत, चुनौती और दायित्व

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की विजयदशमी रैली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संदेश में बहुत सामंजस्यपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सब तरह की विभिन्नताओं का सम्मान करती है। उनका कहना था कि अगर कोई हिन्दू कहलाने में असहज महसूस करता है तो वह खुशी से खुद को 'भारतीय' कह सकता है। उनका यह भी संदेश था कि हिन्दू समाज को 'हम' और 'वह' की मानसिकता से खुद को अलग रखना है और समुदायों के बीच उत्तेजना फैलाना अस्वीकार होना चाहिए। संघ का प्रभाव तो पहले से ही था, पर जिस तरह भागवत उसे नई दिशा दे रहे हैं उससे प्रासंगिकता और बढ़ रही है। सोशल मीडिया और एआई के ज़माने में पुराने कई विचार बदल रहे हैं। इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि खाकी निक्कर चले गई और जिस संगठन का नागपुर मुख्यालय सादगी के लिए जाना जाता है, ने दिल्ली में चमकता हाईटेक कार्यालय बना लिया है। समय के साथ बदलने की उनकी क्षमता से संघ के इतिहास में भागवत का विशेष स्थान मिलेगा। पहली बार लाल किले से देश के किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस की प्रशंसा की है, पर जहां इतना महत्व मिल रहा है वहां दायित्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि जम गई मानसिकता और विचारधाराओं को बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। 2009 में मोहन भागवत संघ के प्रमुख बने थे। उन्हीं के कार्यकाल में नरेन्द्र मोदी का उत्थान हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व क़ायम हो गया। इस दौरान संघ के प्रमुख लक्ष्य, धारा 370 हटाना या अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना, पूरे हो गए। यह सब काम सरकारी, संसदीय या न्यायिक कदमों से शांतिमय ढंग से पूरे हुए। आभास मिला कि भाजपा और आरएसएस के बीच पूर्ण सामंजस्य है, पूर्व में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां तक कह दिया कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम 'सक्षम' हैं, तो भागवत ने भी बताने में देर नहीं लगाई कि «सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए»। वह तो मोरोपंत पिंगले का ज़िक्र करते हुए कह चुके हैं कि जो सार्वजनिक जीवन में हैं उन्हें 75 वर्ष के बाद दूसरों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। बाद में उन्होंने अपनी बात को कुछ संशोधित कर दिया और 75 वर्ष की आयु पार करने पर न नरेन्द्र मोदी और न ही मोहन भागवत ही रिटायर हुए हैं। वैसे, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो रिटायर होने की ज़रूरत भी नहीं। जब जेपी नड्डा जिनका कार्यकाल डेढ़ साल पहले खत्म हो चुका है, के उत्तराधिकारी के बारे पूछा गया कि क्या संघ से मतभेद के कारण मामला लटक रहा है तो भागवत का कटाक्ष था कि हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? पर यह तो स्पष्ट है कि भागवत और उनके संगठन ने यह फ़ैसला कर लिया है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार से बेहतर विकल्प उनके पास नहीं है और वह चाहेंगे कि मोदी 2029 का चुनाव भी लड़ें। पूर्व संघ सरचालक के. सुदर्शन का वाजपेयी सरकार के साथ लगातार झगड़ा चलता रहा। उन्होंने जसवंत सिंह को वित्तमंत्री नहीं बनने दिया था। मीडिया के सामने आकर वाजपेयी और अडवाणी के इस्तीफ़े मांग लिए थे। सम्बंध बिल्कुल टूट गए, और सरकार ने संघ की परवाह करना छोड़ दिया था। जसवंत सिंह को भी वित्त मंत्री बना दिया गया। पर आज दोनों संगठनों के रिश्ते ऐसे हैं कि ऐसे सीधे टकराव की कोई सम्भावना नहीं। लोकसभा चुनाव में जो धक्का पहुंचा था ने भाजपा नेतृत्व को संघ की कीमत समझा दी तो दूसरी तरफ़ संघ को भी अहसास है कि वह कभी भी ऐसी सुविधाजनक स्थिति में नहीं रहे। आरएसएस कितना बदल गया है यह इस बात से पता चलता है कि दिल्ली में शताब्दी समारोह पर मोहन भागवत ने तीन घंटे पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। के. सुदर्शन को छोड़कर अभी तक संघ प्रमुख के विचार विजयदशमी के दिन ही सुनने को मिलते थे। यह भी दिलचस्प है कि संघ प्रमुख के भाषण का अनुवाद इंग्लिश, स्पैनिश और फ्रेंच में किया गया और आमंत्रित मेहमानों में विदेशी पत्रकारों और राजदूतों में चीन के राजदूत भी मौजूद थे।

अर्थात संघ अपनी छवि बदलने में लगा हुआ है कि वह कोई रहस्यमय संगठन नहीं है और दुनिया के लिए खुले हैं। यह भागवत का बड़ा योगदान है। पिछले कई महीनों से वह मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। वह कह चुके हैं कि हिन्दुओं और मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है। वह यह भी कह चुके हैं कि «हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने का प्रयास नहीं होना चाहिए»। आज के माहौल में यह असाधारण साहसी बयान है। काशी और मथुरा के विवादों का ज़िक्र करते हुए उनका कहना था कि जहां संघ किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा वहां इन मंदिरों के लिए किसी भी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कार्यकर्ता आज़ाद हैं। इसे कहा जाता है कि खरगोश के साथ दौड़ भी रहे और शिकारी कुत्तों के साथ शिकार भी कर रहे हैं। शायद वह अपने गर्म ख्याल वालों को संतुष्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो आभास मिलता है कि संघ अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है, पर कहीं अतीत अभी भी रुकावटें खड़ी कर रहा है। वह मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं और कहा है कि «वह हमारा हिस्सा है पर ज़मीन पर यह सद्भावना नज़र क्यों नहीं आती?

देश के आगे बहुत चुनौतियां हैं। आपस में लड़ता-झगड़ता भारत तरक्की नहीं कर सकता। चीन हम से बहुत आगे निकल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारे विरुद्ध हो रहा है। मणिपुर अभी सम्भला नहीं कि लद्दाख जलने लगा है। पूर्व उपकुलपति और क़ानून विशेषज्ञ फ़ैज़ान मुस्तफ़ा का लिखना है, आरएसएस चीफ़ वह व्यक्ति हैं जो नफ़रत और उन्माद के इस माहौल में विवेक, सहिष्णुता, भाईचारा जो हिन्दू धर्म का मूलतत्व है, को क़ायम कर सकते हैं»। मोहन भागवत की स्थिति विशिष्ट है। वह पहले संघ सरचालक हैं जिनका मुस्लिम नेताओं के साथ खुला संवाद है। उन्हें समाज को सही रखने में सक्रियता से योगदान देना होगा। सदियों से चली आ रही हमारी विभिन्नता को बचाकर रखना है। कोई भी राष्ट्र अपने अतीत की ज्यादतियों को लेकर लगातार उबलता नहीं रह सकता। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र खोदने की धमकी दी थी। हमने भविष्य का निर्माण करना है या गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं? हम कब तक सदियों पुरानी शिकायतों और रोष को खाद और पानी देते रहेंगे? देश में पहले से अधिक अविश्वास, तनाव और व्यग्रता है। पिछले कुछ दिनों में कानपुर, बरेली, जालंधर, कटक आदि में साम्प्रदायिक टकराव या तनाव हो कर हटा है। मुख्य न्यायाधीश पर 'सनातन धर्म' के नाम पर हमले का निन्दनीय प्रयास बताता है कि धर्म के स्वयंभू ठेकेदार समाज को गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकना है। हमें आगे देखना है, पीछे नहीं, जो राजनीतिक नेता हैं, उनका दृष्टिकोण दूसरा होता है। उन्होंने चुनाव लड़ना है, वोट लेना है। हर राजनीतिक दल निंदा करते हुए भी अंग्रेजों की 'डिवाइड एंड रूल' की नीति पर चलते हैं। जाति जनगणना का यही मकसद है, पर देश किसी भी संगठन या दल या व्यक्ति से ऊपर है। मोहन भागवत की ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। वह प्रमाण दे चुके हैं कि उनकी सोच संकीर्ण नहीं है। उन्हें उधर रही नफ़रत और असहिष्णुता को रोकने की कोशिश करनी है। वह जानते हैं कि साम्प्रदायिक झगड़े देश का अहित करते हैं, पर कहीं 'इतिहास की हिचकिचाहट' उन्हें रोक देती है। उनकी विरासत उनके लिए चुनौती है। उन्हें इससे ऊपर उठना है। समाज को सही दिशा कोई ग़ैर राजनीतिक व्यक्ति ही दे सकता है। मुझे मोहन भागवत के सिवाय और कोई नज़र नहीं आता। यह उनका राष्ट्रीय दायित्व भी बनता है।

सम्पादकीय...

बगराम रणनीति

आज के दौर में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। कूटनीति में धुर विरोधी दोस्त हो जाते हैं और पक्के दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प के मनमाने रवैये को देखते हुए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने ट्रम्प की दादागिरि का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। जिसका परिणाम मास्को फार्मेट की बैठक में दिखाई ? दिया। मुद्दा था अफगानिस्तान का वो बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका के सैन्य अड्डे के तौर पर चर्चा में था। कुछ दिन पहले ट्रम्प ने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान से बगराम एयरबेस वापिस मांगा था और धमकी दी थी कि अगर बगराम हवाई अड्डा अमेरिका को वापिस नहीं किया गया तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। तालिबान ने ट्रम्प की मांग को ठुकरा दिया था और साफ कहा था कि अफगानिस्तान किसी भी हालत में अपनी जमीन अमेरिका को नहीं सौंपेगा। बगराम एयरबेस दुनिया के सबसे बड़े एयरबेसों में से एक है और वह चीन के परमाणु हथियार बनाने के स्थान से एक घंटे की दूरी पर है। ट्रम्प इस एयरबेस को दोबारा हासिल कर चीन के प्रभाव को बेअसर करना चाहते हैं। वैसे सच यही है कि बगराम वास्तव में 20 साल तक अमेरिकी सेना के बेस का केंद्र था। 9/11 को ट्विन टावर्स पर आतंकी हमले के बाद जब अमेरिकी सेना अलकायदा और उसके साथ-साथ तालिबान के खिलाफ जंग कर रही थी, तब अमेरिकी ऑपरेशन का संचालन बगराम से ही हो रहा था। हालांकि, बगराम एयरबेस का मूल निर्माता सोवियत संघ था, 1950 के दशक में काबुल में राजशाही के दौरान जाहिर शाह के शासन में इसका निर्माण हुआ था। 1980 के दशक में ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से पीछे हटने का फैसला किया। 2001 में अमेरिका के 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' अभियान की शुरूआत के बाद बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में उसकी सैन्य शक्ति का केंद्रीय स्थल बन गया। हालांकि बगराम को वापस हासिल करना सिर्फ ट्रम्प के इस स्वयं घोषित दृष्टिकोण के बारे में नहीं है कि इस कदम के जरिए चीन के खतरे से निपटा जाए। ये उन व्यापक क्षेत्रीय चुनौतियों को भी सामने लाता है जो अगस्त 2021 से चल रही हैं। अगस्त 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल में बगराम से बहुत ही नाटकीय और अराजक परिस्थितियों में अमेरिकी सेना की वापसी का आयोजन किया गया था। 30 अगस्त, 2021 को अमेरिका का आखिरी सैनिक अमेरिकी वायुसेना के सी-17 परिवहन विमान से स्वदेश रवाना हुआ। ये वही समय था जब अफगानिस्तान को दोबारा तालिबान के हाथों सौंप दिया गया। अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान में करीब दो दशक लंबा युद्ध लड़ा लेकिन ये जंग किसी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंची। मास्को फार्मेट की बैठक में हुए अचानक घटनाक्रम में भारत ने भी तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बगराम एयरबेस पर कब्जा करने के प्रयास का विरोध किया। यह घटना तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा से कुछ दिन पहले हुआ है। मास्को फार्मेट के संयुक्त बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान और पड़ोसी राज्यों में अमेरिका द्वारा सैन्य बुनियादी ढांचे को हासिल करने के प्रयास अस्वीकार्य है क्योंकि यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। ट्रम्प की जिद के खिलाफ भारत, पाकिस्तान, तालिबान, चीन और रूस एकजुट हो गए हैं। ट्रम्प को साफ-साफ कह दिया गया है कि बगराम एयरबेस पर कब्जा करने का सपना मत देखें। अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में कोई विदेशी सैन्य बेस बनाना बर्दाश्त नहीं होगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है। खासकर भारत की नजर से देखें तो। क्योंकि भारत ने पहली बार इतने खुले तौर पर अमेरिका का विरोध किया है। वो भी तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा से ठीक पहले। यानी भारत ने अब साफ संदेश दुनिया को दे दिया है। यह नया भारत है, जहां उसे गलत लगेगा खुलकर बोलेगा। भारत तालिबान के विदेश मंत्री की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना का विरोध करके एक दुर्लभ कदम उठाया है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है लेकिन वह मानवीय और विकास कार्यों में सहायता प्रदान करता रहा है। अब, दिलचस्प बात यह है कि मुत्ताकी की पहली भारत यात्रा से पहले जो किसी तालिबान विदेश मंत्री के लिए ऐतिहासिक पहली यात्रा है। इसके पहले भारत भी ट्रम्प की योजना का विरोध करने में शामिल हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के संबंध वैदिक युग से ही हैं क्योंकि गांधार कभी भारत का हिस्सा ही माना जाता था। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है लेकिन भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर सहायता दी है। सड़कें, बांध, स्कूल, अस्पताल और संसद भवन भारत ने ही बनाकर दिए हैं। तालिबान शासन के बावजूद भारत ने खाद्यान्न, दवाइयां, भूकम्प सहायता, कोविड वैक्सीन और अन्य जरूरी सामग्री भेजकर उसे मानवीय सहायता प्रदान की है। तालिबान को भी इस बात का अहसास है कि भारत से दूरी बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है और भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए तालिबान से संबंधों का इच्छुक है।

बिहार में बजा चुनावी बिगुल, किसकी पूरी होगी आस, किसकी टूटेगी उम्मीद

उमेश चतुर्वेदी

हर बार की तरह बिहार विधानसभा का मौजूदा चुनाव उन सभी लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आया है, जो खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं.. उनके समर्थकों की भी उनकी कामयाबी से आस लगी है। कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जिसकी मेहनत उस दल की जीत या हार पर निर्भर करती है, जिससे उसकी प्रतिबद्धता जुड़ी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे प्रशांत किशोर को है। उम्मीद तो तेजस्वी यादव को भी है। उन्हें लगता है कि इस बार उनके नाम के बाद अतीत में लगे उप विशेषण से मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद उस बीजेपी को भी है, जो अपने सहयोगी की तुलना में संख्या बल में ताकतवर होने के बावजूद छोटे भाई की भूमिका निभाने को मजबूर रही है। आस तेजप्रताप को भी है कि वे लालू-राबड़ी की छाया से दूर होने के बावजूद चुनावी मैदान में कमाल दिखाने में वे सफल रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भी ऐसी ही उम्मीदें है। उसे भावी सरकार में हिस्सेदारी की आस है। लेकिन अन्य दलों की तुलना में उसकी उम्मीद कुछ अलग भी है। उसे लगता है कि अगर इस चुनाव में तेजस्वी की अगुआई वाले उसके गठबंधन ने मोदी-नीतीश की जोड़ी को पटखनी दे दी तो दिल्ली के तान तक की उसकी यात्रा आसान हो जाएगी। उम्मीदें खोखली नहीं होतीं। उसका कुछ ठोस आधार भी होता है। इस लिहाज से देखें तो हर पार्टी और उसके बड़े नेताओं की आस के कुछ ठोस आधार है। तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके गठबंधन में शामिल कांग्रेस के चलते उनके पारंपरिक मुस्लिम-यादव गठजोड़ को राज्य के सवर्ण तबके के एक वर्ग का वोट मिल सकता है। पिछले चुनाव में उनका गठबंधन नीतीश की अगुआई वाले गठबंधन की तुलना में महज साढ़े सोलह हजार के करीब वोटों से ही पिछड़ गया था। उन्हें लगता है कि इस बार इस कमी को ना सिर्फ उनका गठबंधन पूरा कर लेगा,बल्कि आगे भी निकल जाएगा। लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि पिछली बार चिराग पासवान की अगुआई वाली लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर लड़ रही थी। तब उनका अघोषित और घोषित-दोनों उद्देश्य नीतीश कुमार को पटखनी देना था। इसमें वे पूरी तरह कामयाब तो नहीं हुए, अलबत्ता नीतीश के नतीजों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। नीतीश की पार्टी को महज 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार चिराग नीतीश के साथ हैं। अंदरखाने में भले ही वे नीतीश का साथ नहीं दे रहे हों, लेकिन करीब दस फीसद पासवान वोटरों का आधार एनडीए को मुहैया करा रहे हैं। इसलिए तेजस्वी को इस बार कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ठोस वोट बैंक में गहरी सेंध लगानी होगी। तेजस्वी के लिए राहत की बात यह है कि सीमांचल की 28 सीटों पर उन्हें चुनौती देने वाली एआईएम इस बार उनसे गठबंधन करने के लिए लालायित है। अगर बात बन जाती है तो तेजस्वी के गठबंधन के लिए चुनावी वैतरणी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी की राह का एक बड़ा रोड़ा उनके बड़े भाई तेजप्रताप हैं। जिन्हें उनकी दो बहनों का परोक्ष साथ भी मिल रहा है। इससे बिहार के उनके कोर वोटरों में संदेश गया है कि परिवार में सबकुछ ठीक नहीं है। अगर तेजस्वी के साथ यादव युवाओं का एक वर्ग खड़ा हो गया तो ओवैसी के आने से मिलने वाले फायदे जितना तेजस्वी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही बात नीतीश कुमार की तो इस बार का चुनाव एक तरह से उनका आखिरी चुनाव है। हालांकि पिछली बार यानी 2020 में जब वे चुनावी चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे थे तो उन्होंने कुछ सभाओं में पिछले ही चुनाव को आखिरी बता दिया था। यह बात और है कि इस बार अभी तक ऐसा उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया है। लेकिन बिहार के सियासी और लोक गलियारों में जिस तरह उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हैं, उससे माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव एक तरह से उनका आखिरी चुनाव होगा। राजनीतिक दुनिया में यह भी माना जा रहा है कि इस बार वे बीजेपी से यह गारंटी चाहेंगे कि उनके बेटे निशांत का नेतृत्व स्थापित हो जाए। निशांत ने कुछ महीने पहले राजनीतिक सक्रियता दिखाकर ऐसा संकेत भी दिया था। हालांकि कुछ अरसे से उन्होंने सियासी चुप्पी ओढ़ ली है। उनके इस रूख से माना जा रहा है कि बीजेपी से अंदरखाने में किसी ठोस बिंदु पर बातचीत हो चुकी है।

हो सकता है कि निशांत विधानसभा का चुनाव ना लड़ें। लेकिन वे चुनाव बाद विधान परिषद में ठीक उसी तरह आ सकते हैं, जैसे उनके पिता आए। याद कीजिए, 2005 के जिस विधानसभा चुनाव में विजय के साथ नीतीश ने लालू राज को उखाड़ फेंका था, उस बार भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और विधान परिषद के सदस्य के नाते उन्होंने सरकार की अगुआई की थी। इस बार के चुनाव में जनता दल यू एकजुट तो दिखेगा, लेकिन चुनाव मैदान में सबसे ज्यादा सवालों का सामना अशोक चौधरी को करना होगा। जिनके भ्रष्टाचार की गाथा को प्रशांत किशोर लोकमानस के बीच पहुंचा चुके हैं। उनकी ही तर्ज पर बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री बने मुरेठाधारी सम्राट चौधरी के लिए भी खुद का बचाव करना मुश्किल होगा, जिनके शैक्षिक प्रमाण पत्र और हत्या के एक आरोप में बरी होने को प्रशांत किशोर ने बिहार का सवाल बनाकर रख दिया है। बीजेपी इस बार चाहती है कि वह राज्य में बड़े भाई की भूमिका में रहे। बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद ही वह राज्य की सर्वोच्च पार्टी बन सकती है। 1967 में समाजवादियों के साथ उसने जहां भी सरकार बनाई, उन राज्यों में बाद के दिनों में वह ना सिर्फ नंबर एक बन गई,बल्कि साथी समाजवादी दूर कहीं पीछे छूटते नजर आए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा और कर्नाटक इसके उदाहरण हैं। लेकिन बिहार में अब भी वह खुद के दम पर अपना वजूद स्थापित करने से दूर है। इस बार बीजेपी चाहेगी कि राज्यमें उसकी अगुआई में सरकार बने। इसके लिए उसने अपने दो बड़े कद्दावर रणनीतिकारों धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े को मैदान में उतार दिया है। दोनों ने बिहार में अपने ढंग से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मैथिली की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी एक तरह से अपना उम्मीदवार घोषित कर ही चुकी है। सत्ता पर काबिज होने और राज्य की नंबर एक सियासी पार्टी बनने के लिए मोदी-शाह के युग में पार्टी ने नई रणनीति अख्तियार की है। वह लोकप्रिय चेहरों को अपने साथ जोड़ने में देर नहीं लगाती। वैचारिक रूप से विरोधी रहे लोगों को भी अपने पाले में लाने में उसे गुरेज नहीं रहा। बशर्ते कि उनके आने से पार्टी को दूरगामी राजनीतिक फायदा मिलता दिख रहा हो। मैथिली ठाकुर का अतीत ऐसा नहीं है। मिथिला के लोक रंग में पली मैथिली एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक हिंदुत्व की राजनीति की नजदीकी ही लगती है। चुनाव के दौरान बीजेपी ऐसे कई और चेहरों पर दांव लगा सकती है। बीजेपी को उम्मीद अपने मजबूत रणनीतिक वोट बैंक पर है। अति पिछड़ों और सवर्ण तबके में उसकी पकड़ अच्छी है। कभी पिछड़ावादी राजनीति जिस समुदाय को भूराबाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ कहकर हिकारत का भाव दिखाती थी, उसे यह वर्ग भूला नहीं है।

हालांकि हाल के दिनों में बीजेपी की ओर से पिछड़ावादी राजनीति को बढ़ावा देने और उसी समुदाय से नेतृत्व उभारने के चलते सवर्ण तबके का एक वर्ग नीतीश-बीजेपी जोड़ी से नाखुश भी है। लेकिन यह भी तय है कि जैसे इस वर्ग को लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल की अगुआई वाला गठबंधन जीत रहा है, एकजुट होकर बीजेपी-नीतीश गठबंधन को टूटकर वोट डालेगा। मुसहर और अति दलित जातियां बीजेपी के साथ नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में कोइरी-कुर्मी की जोड़ी को लवकुश कहा जाता रहा है। नीतीश बेशक अपनी बिरादरी कुर्मी के ही नेता नहीं माने जाते, लेकिन कुर्मी समुदाय उन्हें ही अपना नेता मानता है। कुशवाहा यानी कोईरी वर्ग के नेता उपेंद्र कुशवाहा इसी गठबंधन में हैं। चिराग भी मजबूती के साथ खड़े हैं। लिहाजा जाति और धर्म की कीमियागिरी वाली बिहारी राजनीति में बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन के लिए यह जातीय मसाला बड़ी काम की चीज है। इस बीच कई लोगों की उम्मीद की किरण प्रशांत किशोर बनकर उभरे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें सिर्फ सवर्ण तबके के युवाओं का समर्थन हासिल है। लेकिन जमीनी स्तर पर निगाह रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेशक प्रशांत किशोर के समर्थक युवाओं में सबसे बड़ी संख्या सवर्ण युवाओं की है। लेकिन अन्य वर्ग के भी पढ़े-लिखे युवा भी प्रशांत किशोर के साथ हैं। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार, जातिवाद और धर्म केंद्रित राजनीति में प्रशांत किशोर बिहार के लिए उम्मीद की नई किरण हैं। जिस तरह 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में राजनीतिक और चुनावी विश्लेषक अरविंद केजरीवाल को विशेष तवज्जो नहीं दे रहे थे, कुछ वैसी ही सोच प्रशांत किशोर को लेकर भी दिख रही है। लेकिन जिस तरह नतीजों में अरविंद केजरीवाल ने लोगों और चुनाव विश्लेषकों को चौंकाया था, हो सकता है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर को लेकर वैसे ही देश-दुनिया को चौंकाने का मौका दे सकती है। इससे बिहार में अपनी साख को दांव पर लगा रहा हर दल चिंतित भी है और परेशान भी। वैसे प्रशांत किशोर का मानना है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में या तो उन्हें 150 सीटें मिलेंगी या फिर दस-पंद्रह। इस लिहाज से देखें तो प्रशांत किशोर जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि नतीजे कुछ ऐसे ही रहें। वैसे अपना आकलन है कि वे बिहार की राजनीति में सेंध लगाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन सरकार बनाने के जादुई आंकड़े को छू पाना उनके लिए कठिन रहने वाला है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी रही है। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहां भले ही देश के बाकी हिस्से की तरह पूरी होती रही हो, लेकिन जाति और धर्म के सांचे में बैठे होने के चलते वह खासा बदनाम भी रही है। प्रशांत किशोर से शुरू में उम्मीद बढ़ी कि वे ऐसी ही राजनीति करेंगे। लेकिन पार्टी गठन के बाद जिस तरह उन्होंने धर्म विशेषकर मुसलमान समुदाय के लोगों को तवज्जो देने की बात करनी शुरू की, नई तरह की राजनीति की उम्मीद जताए बैठे लोगों को उससे थोड़ी निराशा भी हुई।

भारतीय फौज में सिखों को सम्मान

भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी फौज में सिख सैनिक बिना किसी रोक-टोक के अपने धार्मिक चिन्हों के साथ अपनी ड्यूटी कर सकते हैं अन्यथा हर देश में किसी न किसी रूप में कई तरह की पाबंदियों के बीच उन्हें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। अभी हाल ही में अमरीका जैसे देश ने भी एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है जिसके तहत अमरीका की फौज में ड्यूटी करने वालों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी गई है जिसके बाद अब सिख सैनिकों को अगर अमरीका की फौज में कार्यरत रहना है तो उन्हें अपनी दाढ़ी, केश कटवाने होंगे या फिर धार्मिक आजादी और फौज की नौकरी में से किसी एक को चुनना होगा। इस फैसले के बाद से देशभर के सिखों में रोष देखने को मिल रहा है, वहीं हैरानी इस बात की है कि इस आदेश के पारित होने के कई दिन बाद भी अभी तक गुरपतवंत सिंह पन्नू या अन्य किसी खालिस्तानी नेता का कोई बयान इस फैसले के खिलाफ नहीं आया जो कि साबित करता है कि इन्हें सिखों या सिख मर्यादा के से कोई लेना-देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ भारत में आतंक का माहौल पैदा कर उसके एवज में अपनी ऐशो-आराम की जिन्दगी का प्रबन्ध करते हैं। सिख्स फॉर जस्टिस ने ट्रम्प सरकार से अमेरिका में सिख ट्रक ड्राइवरों को उत्पीड़ित समुदाय के रूप में मान्यता देकर उन्हें टैम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए जाने की मांग तो की जा रही है, मगर अमरीकी फौज में सिखों की पहचान खत्म करने पर चुप्पी साधे हुई है जो इनके दोहरे मापदण्ड को दर्शाता है। भारत में भी कई सिख जत्थेबंदियों के द्वारा इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अमेरिका की इस नीति की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि «ये पहली बार नहीं है जब सिखों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी पगड़ी हटाने और सिख सैनिकों को अपमानित करने की घटनाएं हो चुकी हैं। यह फैसला न लोकतांत्रिक है, न ही मानवीय। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी अमरीका के गुरुद्वारा साहिब के प्रबन्धकों और अमरीकी सिखों से सम्पर्क कर इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय फौज में सिख सैनिकों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। पगड़ीधारी सिख भारतीय फौज में उच्च पदों पर आसीन रहे हैं और भारत के लोगों की ऐसी भावना भी है कि सिख सैनिकों के रहते उनको मुल्क को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता। एक समय तो ऐसा था जब भारतीय फौज में सबसे अधिक गिनती सिख सैनिकों की ही रहती थी, मगर कुछ समय पूर्व राज्य की जनसंख्या के हिसाब के भर्ती होने और सिख युवकों के विदेशों की ओर पलायन करने के चलते इसमें कुछ कमी देखी गई है, मगर आज भी सिख रैजीमेंट से लेकर शायद फौज की हर रैजीमेंट में सिख फौजी पूर्ण सिख मर्यादा का पालन करते हुए कार्यरत हैं, इसलिए अगर सिखों को फौज की ही नौकरी करनी है तो विदेशों के बजाए उन्हें अपने देश की फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करनी चाहिए। गुरु गोबिन्द सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोड़ा साहिब तख्त पटना साहिब में सुशोभित होंगे – गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिन्द सिंह जी तक सभी गुरु साहिबान की अनेक निशानियां आज भी कई लोग संभाल कर रखे हुए हैं, मगर इसमें से कौन सी निशानियां वाकय ही गुरु साहिबान की है, यह तयकर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसका फायदा उठाकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पास रखी वस्तुओं को गुरु काल की बताकर संगत की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं।

बीते दिनों केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी परिवार के द्वारा दावा किया गया कि उनके परिवार के पास गुरु गोबिन्द सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पैर के जोड़ा साहिब पिछले 300 सालों से सुरक्षित रखे हुए है जिन्हें 1947 में विभाजन के दौरान उनके पिता होशियार सिंह पुरी, तत्कालीन समय में लेफ्टिनेंट, गलियों से इसे बचाकर लाए और तब से इन्हें दिल्ली के करोल बाग रोहतक रोड स्थित उनके परिवार के यहां रखा गया था मगर उनके चचेरे भाई के देहांत के बाद परिवार ने इन्हें किसी ऐतिहासिक गुरुघर को सौंपने का निर्णय लिया गया, मगर इससे पूर्व हरदीप सिंह पुरी और उनके परिवार के द्वारा एक कमेटी का गठन कर इसकी गंभीरतापूर्वक जांच करवाई गई हालांकि इन जोड़ा साहिब का जिक्र महान कोश किताब में भाई कहान सिंह के द्वारा भी किया गया है। इसकी प्रमाणिकता के लिए इस धरोहर की कार्बन टेस्टिंग भी करवाई गई, जांच रिपोर्ट के टाइमिंग मैच करने की रिपोर्ट आई। इसके बाद यह रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपी गई और उन्हें "जोड़ा साहिब" के दर्शन भी करवाए गए। स. हरदीप सिंह पुरी और उनके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा यह तय किया गया कि "जोड़ा साहिब" को तख्त पटना साहिब कमेटी को सौंपा जाए। परिवार के फैसले के बाद तख्त पटना कमेटी ने इन्हें दिल्ली से एक धार्मिक यात्रा के रूप में तख्त पटना साहिब ले जाने की योजना बनाई जा रही है और इसके बाद इन्हें तख्त पटना साहिब संगत दर्शन के लिए रखा जाएगा, हालांकि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इन्हें गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में रखने की इच्छुक थी। सिख श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझकर दिए गए पाकिस्तान के वीजा –हर साल गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के ननकाणा साहिब के लिए भेजा जाता है, मगर पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों में बढ़ते तनावपूर्ण माहौल के चलते इस बार भारत की सरकार ने वीजा न देने का फैसला लिया था, मगर बाद में सिखों की भावनाओं को समझते हुए सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया और 3000 श्रद्धालुओं को वीजा देने का मन बनाया, हालांकि इस बार वीजा मंजूरी केवल प्रमाणित सिख जत्थेबं?दयों के द्वारा भेजे जाने वाले वीजा फार्मों को ही मिलेगी अन्यथा इससे पूर्व कई निजी संस्थाएं भी वीजा लेने में कामयाब हो जाया करती थी। पाकिस्तान की ओर से तो कई माह पूर्व ही इस पर निर्णय लेकर बेसब्री से भारत के फैसले का इन्तजार किया जा रहा था, क्योंकि भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं के दम पर उनका कारोबार चलता है, मगर अफसोस कि जब भी भारत से श्रद्धालुगण पाकिस्तान जाते हैं उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर आज तक पाकिस्तान प्रशासन के द्वारा उन दिक्कतों को दूर करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

पाकिस्तान विरोधी पॉल कपूर को ट्रंप ने दक्षिण एशिया का प्रभारी बनाकर इस्लामाबाद को झटका दे दिया

अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर एस. पॉल कपूर की नियुक्ति न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक राहत के रूप में देखी जा रही है। पॉल कपूर, जो लंबे समय से दक्षिण एशियाई सुरक्षा, परमाणु नीति और आतंकवाद पर अपने कठोर विश्लेषणों के लिए जाने जाते हैं, अब उस पद पर आसीन हुए हैं जहाँ से अमेरिका की भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रति नीतियाँ तय होती हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय आई है जब अमेरिकी नीतियों में भारत के प्रति तनाव दिखने लगा था– विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क और व्यापारिक मतभेदों के कारण। ऐसे में कपूर की नियुक्ति अमेरिका-भारत संबंधों के लिए 'कूटनीतिक मरहम' के रूप में मानी जा रही है। कौन है पॉल कपूर और क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं? यदि इस पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में जन्मे पॉल कपूर भारतीय पिता और अमेरिकी माता के पुत्र हैं। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और लंबे समय से अमेरिकी नौसेना के पोस्टग्रेजुएट स्कूल तथा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। वह उन कुछ विद्वानों में से हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति पर गहरी अकादमिक और व्यावहारिक समझ बनाई है। पाकिस्तान की नीतियों को उन्होंने राज्य प्रायोजित उग्रवाद« कहा है, न कि अस्थिरता की परिणति। यह दृष्टिकोण अमेरिका के भीतर पाकिस्तान के प्रति एक कठोर रुख की वकालत करता है। कपूर का यह विश्लेषण भारत के लिए राहतकारी है, क्योंकि अब दक्षिण एशिया मामलों में निर्णय-प्रक्रिया ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो पाकिस्तान की «दोहरी नीति को अच्छी तरह समझते हैं। इससे पहले कपूर ट्रम्प प्रशासन के नीति नियोजन विभाग में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने इंडो-पैसिफिक रणनीति« के निर्माण में भूमिका निभाई थी। यानी वह न केवल एक अकादमिक हैं, बल्कि नीति-निर्माण की मशीनरी से भी भली-भांति परिचित हैं। उनकी नियुक्ति से यह स्पष्ट संकेत जाता है कि अमेरिका अब दक्षिण एशिया को केवल पाकिस्तान या अफगानिस्तान के संदर्भ में नहीं, बल्कि भारत-केंद्रित दृष्टि से देखना चाहता है। कपूर की नियुक्ति भारत के लिए राहत क्यों है? यदि इस पर चर्चा करें तो हमें यह देखना होगा कि पॉल कपूर का विचार है कि पाकिस्तान का आतंकवादी ढाँचा कोई आकस्मिक तत्व नहीं, बल्कि उसकी «राष्ट्रीय रणनीति« का अभिन्न हिस्सा है। इसका सीधा अर्थ है कि वे अमेरिका के भीतर पाकिस्तान के प्रति किसी «नरमी« के पक्षधर नहीं हैं। उनकी सोच के अनुसार, जब तक इस्लामाबाद आतंकवाद को नीतिगत औज़ार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक दक्षिण एशिया में स्थायी शांति असंभव है। भारत के दृष्टिकोण से यह अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि बीते वर्षों में अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में कई बार ऐसे संकेत मिले थे कि वॉशिंगटन इस्लामाबाद को फिर से रणनीतिक महत्व देने लगा है–खासकर अफगान मोर्चे पर। कपूर की उपस्थिति इस संतुलन को भारत की ओर झुका सकती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटे ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैराडाइज एमा. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटे, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

कांशीराम जी की जयंती पर कांग्रेस की दलित एकता का संकल्प

गोरखपुर।

कांग्रेस दलित जोड़ो कार्यालय चारु चंद्र पूरी गोरखपुर में अपराह्न 1:00 बजे सामाजिक न्याय के पुरोधा और बहुजन समाज के नायक मान्यवर कांशीराम जी की जन्म जयंती के अवसर पर एक प्रभावशाली स्मृति सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल कांशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर था, बल्कि दलित सशक्तिकरण और एकता का एक जीवंत मंच भी साबित हुआ। सभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्ञान पांडेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता महेंद्र मोहन उर्फ गुड्डू तिवारी ने की। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और महिला नेताओं की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कांशीराम जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुई।कार्यकर्ताओं ने 'जय भीम, जय भारत' के नारों से माहौल को गूंजायमान कर दिया। वक्ताओं ने कांशीराम जी के 'जाति तोड़ो, एकता जोड़ो' के मंत्र को दोहराते हुए उनके सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। मुख्य अतिथि ज्ञान पांडेय ने अपने संबोधन में कहा, मान्यवर कांशीराम ने दलित और वंचित समाज को संगठित कर एक नई क्रांति की नींव रखी। उनका सपना था एक ऐसा भारत, जहां बराबरी और सम्मान हर व्यक्ति का हक हो। आज हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाकर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एकजुट होना होगा। उन्होंने कांग्रेस के दलित जोड़ो अभियान को कांशीराम

जी की विरासत को आगे बढ़ाने का एक मजबूत कदम बताया। अध्यक्ष महेंद्र मोहन उर्फ गुड्डू तिवारी ने जोश भरे अंदाज में कहा, 31वीं सदी के महानायक, दलित, शोषित, पीड़ित व उपेक्षित समाज के हक, अधिकार और न्याय के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। उनके द्वारा प्रवलित परिवर्तन की योति ने बहुजन समाज को नई दिशा दी। उनके विचार, सिद्धांत और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उनके पदचिह्नों पर चलकर हम सामाजिक समानता और न्याय की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। ने कांशीराम जी को 'बहुजन नायक' करार देते हुए कहा,÷उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है।, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंद्रप्रकाश राय जी ने कहा आरक्षण और सामाजिक समानता की लड़ाई में हमें और मुखर होना होगा दलित वंचित लोगों की हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

युवा नेता सोनू कुमार पासवान ने डिजिटल युग में कांशीराम जी के विचारों को सोशल मीडिया के जरिए जन-जन तक पहुंचाने की अपील की और उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं। कांशीराम जी के सपनों को साकार करने में उनकी हिस्सेदारी अनिवार्य है। सभा में महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने माहौल को और ऊर्जावान बनाया। राजीव गांधी पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव विजय कुमार राव, कांग्रेस दलित जोड़ो गोरखपुर के अध्यक्ष प्रभु कन्नौजिया, प्रदेश महासचिव अभिजीत पाठक, छोटे लाल भारती, राजेंद्र यादव,अधिवक्ता आकाश पासवान, मनीष गौतम राधेश्याम सिंह (कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष), सोनू निषाद, ललित निषाद, लाल मोहन पासवान, गुलशन, गुड़िया, ध्रुव गुप्ता, वरिष्ठ नेता राजू सिंह सहित कई नेताओं ने अपने विचार साझा किए। महिला कार्यकर्ताओं ने कांशीराम जी के संघर्ष को याद करते हुए सामाजिक बदलाव में अपनी सक्रिय भूमिका पर बल दिया। श्रीमती कमला पासवान ने भावुक होकर कहा, ÷कांशीराम जी ने हमें सम्मान की राह दिखाई। हम उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कटिबद्ध है।

90-दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान में 111 पुराने वादों का हुआ निस्तारण

देवरिया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मध्यस्थता एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में संचालित 90-दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान (01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025) के अंतर्गत जनपद में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन और सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में इस विशेष अभियान के दौरान प्राप्त 974 लंबित वादों में से 111 वादों का सफल निस्तारण कराया गया। निस्तारित मामलों में 30 वर्ष पुराना एक वाद, 25 वर्ष पुराने नौ वाद, 20 वर्ष पुराने दस वाद, तथा वर्ष 2006 से अब तक के 91 वाद शामिल रहे। इन वादों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, आपराधिक समझौता योग्य मामले,

उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, भूमि विवाद, बेदखली एवं भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले शामिल थे। अभियान के दौरान स्वयं सचिव मनोज कुमार तिवारी ने सर्वाधिक 38 वादों का निस्तारण किया, जबकि अन्य मध्यस्थों द्वारा 73 मामलों को सुलझाया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल लंबित मामलों को सुलझाने की दिशा में प्रभावी पहल रहा, बल्कि इससे आम जनता में मध्यस्थता को एक भरोसेमंद और

तीन दशक पुराने मामले का भी हुआ समाधान, मध्यस्थता बनी न्याय का प्रभावी विकल्प — मनोज कुमार तिवारी

वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में स्वीकारने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। श्री तिवारी ने कहा कि, इस अभियान ने यह सिद्ध किया है कि संवाद, सहयोग और आपसी समझ से विवादों को सुलझाया जा सकता है। इससे न केवल अदालतों पर बोझ कम होता है, बल्कि समाज में सद्भाव और आपसी विश्वास भी मजबूत होता है। अभियान की सफलता पर उन्होंने मध्यस्थगण, अधिवक्ताओं और वादकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद के कोने-कोने में मध्यस्थता की भावना को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

गीतकार शैलेन्द्र असीम होंगे सृजनश्री अलंकरण से सम्मानित

हाटा मोतीचक विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम रोहुआ मछरगावाँ निवासी साहित्यकार शैलेन्द्र पाण्डेय असीम को बाबूजी मनोहर सिंह यादव स्मृति सृजनश्री अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। प्रज्ञा हिन्दी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा सप्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रज्ञा सम्मान समारोह 2025 के चयन के परिणाम की घोषणा 30 सितम्बर दिन मंगलवार को एस आर ज्ञानेश्वरी इण्टर कॉलेज आसफाबाद, फिरोजाबाद के सभागार में ट्रस्ट के स्थायी प्रकल्प अविकल्प प्राण प्रकाशन के चतुर्थ स्थापना दिवस पर आयोजित गीतोत्सव गीत योत्सना कार्यक्रम के दौरान की गई। उक्त अवसर पर, बाबूजी मनोहर सिंह यादव स्मृति सृजनश्री अलंकरण - 2025 (सुप्रसिद्ध गीतकार देवल आशीष की पुण्य स्मृति को समर्पित सृजन परम्परा गीत की गीत सृजन प्रतियोगिता के विजेता हेतु) प्रथम स्थान प्राप्त वरिष्ठ गीतकार डॉ. शैलेन्द्र

प्रियंका दुबे प्रबोधिनी को तृतीय पुरस्कार

असीम को दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही तृतीय स्थान प्राप्त गोरखपुर निवासी कवयित्री डॉ. प्रियंका दुबे प्रबोधिनी को श्रीयुत श्रीपति लाल राठौर स्मृति गीत सृजन प्रतियोगिता नन्दराम राठौर तृतीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि प्रज्ञा हिन्दी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा सप्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रज्ञा सम्मान समारोह दिनांक 7 व 8 फरवरी 2026 को बाबूजी मनोहर

सिंह यादव सभागार आई वी इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश भारत में आयोजित होगा जिसमें पूर्वांचल की इन साहित्यिक विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। असीम जी तथा प्रबोधिनी जी को क्रमशः विजेता तथा द्वितीय उपविजेता का सम्मान प्राप्त होने की सूचना पर सर्वश्री त्रिलोकी त्रिपाठी चंचरीक, चन्देश्वर शर्मा परवाना, एडवोकेट अब्दुल हमीद आरजू, रामजी कुशवाहा, डॉ. मोहन पाण्डेय भ्रमर, मधुसूदन मिश्र, भावना द्विवेदी, चन्द्रहास वर्मा, पी.के.सोनी, अक्षय गिरी, राघवेन्द्र मिश्र अमूल, आदित्य तिवारी सहित अनेक लोगों ने बधाई दी है।

शराब और पशु तस्करी रोकने में विफल, एसपी ने थानाध्यक्ष बनकटा सहित एक आरक्षी को किया निलंबित

देवरिया।

पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने गुरुवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष बनकटा उपनिरीक्षक नवीन चौधरी तथा थाना श्रीरामपुर के चौकी प्रतापपुर पर तैनात आरक्षी उमेश चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मियों पर शराब ठेकेदारों से मिलीभगत करने और बॉर्डर क्षेत्र में अवैध शराब एवं पशु तस्करी को रोकने में विफल रहने के गंभीर आरोप हैं। लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने यह कार्रवाई की। एसपी संजीव सुमन ने कहा कि पुलिस की लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था की मजबूती और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी जारी है। निलंबित दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।

लोकल को वोकल बनाना ही प्रधानमंत्री जी का सपना है — सांसद

कुशीनगर।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो/ "स्वदेशी मेला" 2025 का 15 दिवसीय मेला का शुभारंभ जूनियर हाईस्कूल पडरौना परिसर में सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि यह मेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है। हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित होकर अपने परिश्रम, स्वावलंबन और संस्कृति पर गर्व करता है। आज जब हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं, तो केवल किसी उत्पाद को नहीं, बल्कि अपने किसानों, कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के श्रम को सम्मान देते हैं। ÷लोकल को वोकल÷ बनाना ही प्रधानमंत्री जी का सपना है — और इस मेले के माध्यम से हम सब उस सपने को साकार कर रहे हैं। उन्होंने हस्तशिल्पकारों, उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और आयोजकों को हार्दिक बधाई देते हुए आह्वान किया किया कि आइए, हम सब संकल्प लें कि हर घर, हर दिल में

15 दिवसीय स्वदेशी पहले का हुआ शुभारंभ

स्वदेशी की भावना को प्रबल करेंगे। यही सच्ची देशभक्ति है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि स्वदेशी मेला न केवल हमारे स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन है, बल्कि यह हमारे जिले की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक भी है। इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को एक ऐसा मंच प्राप्त होता है जहाँ वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें और अपने उत्पादों को व्यापक पहचान दिला सकें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस प्रकार के आयोजनों को सदैव प्रोत्साहित करता रहेगा ताकि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सके। उन्होंने शिक्षा को कौशल से जोड़ेंगे त ही आगे बढ़ेंगे । जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कराए जाने क उद्देश्य से भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है जहां पर सस्ते दर पर उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग पार्क, के संबंध में भी जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि सरल प्रक्रिया में विभाग के विभिन्न योजनाओं के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत विकसित यूपी के संबंध में बार कोड स्कैन कर अपनी राय अपना फीड बैक सरकार को अवश्य भेजें । इस अवसर पर मा0 सांसद सहित अन्य जन प्रतिनिधि गण सहित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्टालों का निरीक्षण भी किया गया। उद्योग विभाग द्वारा दर्जी ट्रेड अंतर्गत 06 लाभार्थियों को टूल किट वितरण किया गया तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अंतर्गत 05 लाभार्थियों को 05 - 05 लाख का डमी चेक का वितरण भी किया गया। एक जनपद एक उत्पाद योजना के मार्जिन मनी योजना अंतर्गत एक लाभार्थी को 25 लाख का डमी चेक वितरण किया गया।

आनंद गंगा फार्मेसी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा आयुषी सिंह बनी एक दिन की जीआरपी थाना प्रभारी

भटनी देवरिया।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल के तहत आनंद गंगा फार्मेसी नर्सिंग कॉलेज, भटनी की छात्रा आयुषी सिंह को भटनी रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने की एक दिन की थाना प्रभारी

बनाया गया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष जीआरपी बी.बी. राजभर सहित महिला कांस्टेबल बबीता यादव, ज्योति सिंह, कांस्टेबल प्रमेश यादव व गुड्डू ने थाना प्रभारी बनी छात्रा को पुलिस कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, यात्री सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

थाने के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए आयुषी सिंह ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि इस अवसर से उन्हें समाज में सेवा और सुरक्षा की भावना को और गहराई से समझने का अवसर मिला।यह पहल छात्राओं को नेतृत्व, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना से जोड़ने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम साबित हुई है।

राजू पाठक सैकड़ो सैकड़ो समर्थको के साथ सर्वजन हित पार्टी में हुए शामिल

कुशीनगर। समाजसेवी राजू पाठक समाजवादी पार्टी छोड़कर अपने सैकड़ों साथियों के साथ अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ज्वाईन किये। पिपरा बाजार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पाठक को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नजरुद्दीन भाई, मनुज कुमार,झिनक दिवान, प्रद्युम्न सिंह,ओमप्रकाश गुप्ता,नारायण चौहान,प्रदीप कुशवाहा, हरिओम जायसवाल, नदीम अख्तर, शिवनारायण अग्रवाल, नवीन तुलस्यान, दिवाकर मद्धेशिया, जोखन यादव आदि समर्थक उपस्थित रहे।

26/11 हमलों पर कांग्रेस-भाजपा में तीखी जुबानी जंग, प्रमोद तिवारी बोले- गुजरात सीएम कौन था?

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा जिसमें मोदी ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी की कमजोरी दिखाने की आलोचना की थी। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब 26/11 हुआ था, तब वे 10 आतंकवादी गुजरात के तट से आए थे... तब मुख्यमंत्री कौन थे? आप (प्रधानमंत्री मोदी) थे। वहां जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन 10 आतंकवादियों में से नौ मारे गए और एक को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ, तो क्या किसी ने उन्हें रोका। हमने अपने मुख्यमंत्री को हटा दिया और गृह मंत्री को बदल दिया, लेकिन क्या आपने पहलगाम हमले के बाद अपना गृह मंत्री बदला। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री मोदी ने बुजुर्ग को तत्कालीन कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं हुई है और आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई है। उनका नाम लिए बिना, प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के एक साक्षात्कार का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने 26/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान को यूपीए सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा की थी। हमलों के बाद और शिवराज पाटिल के इस्तीफे के बाद गृह मंत्री बने चिदंबरम ने कहा था कि जवाबी कार्रवाई का विचार उनके मन में आया था, लेकिन सरकार ने वैश्विक दबाव में संयम बरतना चुना। उनकी टिप्पणी का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से यह बताने को कहा कि विदेशी प्रभाव में सुरक्षा कदमों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने का फैसला किसने किया, और कहा कि देश को जानने का अधिकार है। मुंबई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुंबई न केवल आर्थिक राजधानी है, बल्कि भारत के सबसे जीवंत शहरों में से एक है। यही कारण है कि 2008 में आतंकवादियों ने एक बड़े हमले के लिए मुंबई को चुना। लेकिन उस समय सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने कमजोरी का संदेश दिया, आतंकवाद के सामने आत्मसमर्पण का संदेश दिया। उन्होंने आगे कहा, हाल ही में, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे, ने एक साक्षात्कार में कई बातें उजागर कीं। उन्होंने दावा किया कि मुंबई हमले के बाद, हमारी सेनाएँ पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थीं। पूरा देश यही चाहता था। लेकिन उस कांग्रेस नेता के अनुसार, तत्कालीन सरकार ने दूसरे देश के दबाव में भारतीय सेना को कार्रवाई करने से रोक दिया। कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि विदेशी दबाव में यह फैसला किसने लिया, किसने मुंबई की राष्ट्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। देश को जानने का अधिकार है। कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश ने बार-बार जान गंवाकर चुकाई।

तेजस्वी का हर घर नौकरी गारंटी!

सरकार बनी तो 20 दिन में कानून, 20 महीने में सबको जॉब

पटना।

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बड़े चुनावी वादे की घोषणा की, जो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में महागठबंधन सत्ता में आता है, तो बिहार के हर घर से एक ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि हमारी सरकार आने पर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर घर में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला हो। सरकार बनने के 20 दिन के अंदर हम इसके लिए एक नया कानून बनाएँगे और 20 महीनों में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ सरकारी नौकरी न हो। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी ओर से की जाने वाली कई

घोषणाओं में से यह पहली घोषणा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी प्राथमिकता बिहार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें नीतीश कुमार सरकार की तरह बेरोजगारी भत्ता देना। इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि हर बिहारी बदलाव लाने वाला मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वे इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। महागठबंधन सरकार बनाएगा...जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ बेरोजगार युवा न हों। जब तेजस्वी आएंगे, तो वे सभी को रोजगार देंगे। बिहार से बेरोजगारी जड़ से मिटा दी जाएगी। आज से एक उत्सव शुरू हो रहा है...तेजस्वी के साथ, इस बार हर बिहारी मुख्यमंत्री होगा, वे मुख्यमंत्री होंगे - बदलाव लाने वाले। यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग गिड़गिड़ाने वाला मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पिछली महागठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे यादव ने कहा, 20 साल तक उन्होंने राज्य को अपराध, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, अत्याचार और घोटाला दिया। बिहार के लोग इससे तंग आ चुके हैं। सीएम अपने क्षेत्र में नहीं हैं। हमें ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो गिड़गिड़ाए, हमें ऐसा सीएम चाहिए जो शेर की तरह दहाड़े। कोई ऐसा जो बिहार के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ सके और उन्हें न्याय दिला सके। 14 नवंबर को तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की गई है, जिसके लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

कॉलेज में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा, सीएम योगी ने कहा- खेलों से आत्मनिर्भर और सशक्त होगा नया यूपी

झांसी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि स्वस्थ शरीर ही धर्म और राष्ट्र निर्माण का आधार है और खेलों से नया उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में योगी ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए रानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल अब केवल शौक नहीं, बल्कि जीवन को संवारने का सशक्त माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की धरती पर विद्या भारती के 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विद्या भारती देश में भारतीय परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रीयता के प्रति श्रद्धा जगाने वाली अग्रणी संस्था है। 1952 में गोरखपुर में नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित इस संस्था ने आज देशभर में 25 हजार

से अधिक शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से भारतीय मूल्यों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने विद्या भारती के प्रथम छात्र देवेंद्र सिंह को सम्मानित करते हुए कहा कि यह संस्था बिना सरकारी सहयोग के राष्ट्रीय आदर्शों को जीवंत रखने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि झांसी की यह धरती राष्ट्रीयता और शौर्य की प्रेरणा देती है। विद्या भारती के प्रयास देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समारोह में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला। बुंदेली राई नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले शीलू यादव, आदेश सिंह, शहंशाह, बसंत कुमार गोला और संध्या राजपूत को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में अनुशासन ट्रॉफी गोरखपुर प्रांत ग्रामीण की टीम को प्रदान की गई, जबकि ओवर ऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी काशी प्रांत नगरीय की टीम ने अपने नाम की। योगी ने विद्या भारती की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज यह संस्था भारत की परंपरा और संस्कृति को मजबूत करने वालों अग्रणी शक्ति बन चुकी है। 1952 में गोरखपुर की धरती पर राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख द्वारा बोए गए बीज से आज देशभर में 25,000 से अधिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में सेक्युलर दिखने की होड़ ने भारतीय मूल्यों को हाशिए पर धकेला, लेकिन विद्या भारती ने बिना सरकारी सहयोग के गाँव से शहर और वनवासी क्षेत्रों तक शिक्षा का राष्ट्रीय मॉडल खड़ा किया। उन्होंने कहा आज इस वीरभूमि में पहुंचकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मेरी झांसी गुलाम नहीं होगी का संदेश दिया और 23 वर्ष की आयु में बलिदान दे दिया। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को दो बार ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। आज उनके नाम पर भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार और प्रदेश सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्या भारती के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं का इस्तीफा

असम में भाजपा को लगा झटका

डिब्रूगढ़ ।

असम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार के भाजपा सांसद राजेन गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कुल 17 अन्य सदस्यों ने भी पार्टी से अपना त्यागपत्र सौंपा। राजेन गोहेन ने यह फैसला राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया को लिखे पत्र में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी जिम्मेदारियों से तुरंत प्रभाव से हट रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस्तीफा देने वाले अधिकांश सदस्य ऊपरी और मध्य असम से हैं। राजेन गोहेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पार्टी ने असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और स्थानीय समुदायों को धोखा दिया, जबकि बाहरी लोगों को राय में बसने की अनुमति दी। बता दें कि, राजेन गोहेन ने 1999 से 2019 तक नागांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2016 से 2019 तक रेल मंत्रालय में राय मंत्री भी रहे। भाजपा में रहते हुए वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे पेशे से चाय बागान के मालिक भी हैं। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में उनका काफी प्रभाव है। उनके जाने से भाजपा को राय में नुकसान हो सकता है। असम में फिलहाल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा नीत सरकार सत्ता में काबिज है। जबकि पूर्वोत्तर राय असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है।

हमारे लिए अब यह बीता अध्याय है, जूता फेंके जाने के मामले में बोले सीजेआई

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को जूता हमले की घटना पर अपना रुख दोहराया और कहा कि यह एक भुला दिया गया अध्याय है। जूता हमले पर गवई ने कहा कि जो हुआ उससे मैं और मेरे विद्वान भाई बहुत स्तब्ध हैं; हमारे लिए यह एक भुला दिया गया अध्याय है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने गुरुवार को न्यायाधीशों से अदालत में संयम बरतने और कम बोलने का आग्रह किया। 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था और उन पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील राकेश किशोर की सदस्यता समाप्त कर दी, जिन्होंने अदालत कक्ष के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। उन्हें गंभीर कदाचार

का दोषी पाते हुए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एक 71 वर्षीय वकील ने कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की ओर उनके न्यायालय कक्ष में जूता फेंकने का प्रयास किया, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वकील को सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाते हुए सुना गया। अदालती कार्यवाही के दौरान और उसके बाद हुई इस अभूतपूर्व घटना से अविचलित रहे प्रधान न्यायाधीश ने अदालत के अधिकारियों और अदालत कक्ष में मौजूद सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे इसे नजरअंदाज करें और राकेश किशोर नामक दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ दें। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन के साथ पीठ पर बैठे मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि इस सब से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं। इन बातों का मुद्दा पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने मामलों की सुनवाई जारी रखी। बार निकायों, एससीबीए और एससीएओआरए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राजनीतिक दलों सहित वकीलों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे संविधान और समग्र संस्था पर हमला बताया। दिल्ली के मयूर विहार निवासी किशोर से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शीर्ष अदालत परिसर में तीन घंटे तक पूछताछ की और बाद में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न होने पर उन्हें दोपहर 2 बजे जाने दिया गया।

भारत-ब्रिटेन संबंधों में नयी ऊर्जा आ गई है - प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार है और दोनों देशों के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता एवं आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के साथ व्यापक वार्ता के बाद मोदी ने कहा कि भारत-ब्रिटेन संबंधों का आधार लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में स्टार्मर ने कहा कि भारत-ब्रिटेन का संबंध खास है। उन्होंने भारत की विकास गाथा को उल्लेखनीय बताते हुए कहा, ''हम भविष्य पर केंद्रित एक नयी आधुनिक साझेदारी गढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, ''हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन संघर्ष और गाजा मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। ब्रिटिश नेता ब्रिटेन के 125 सबसे प्रमुख व्यापारिक नेताओं, उद्यमियों और शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बुधवार सुबह दो दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंचे। स्टार्मर की भारत यात्रा दोनों देशों द्वारा एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के कई महीने बाद हुई है।

25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी, पूरे विश्व को देंगे राम मंदिर पूरा होने का संदेश

अयोध्या ।राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि राम मंदिर सिर्फ राष्ट्र मंदिर नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय राम मंदिर बने। यह बात सभी क्षेत्र, सभी वर्ग और सभी विचारधारा के लोग स्वीकार करें, ऐसा प्रधानमंत्री का सपना है और जब ये सपना साकार होता दिखाई पड़ता है तब मन को संतोष मिलता है। 25 नवंबर अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद मोदी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के शिखर पर 21 फीट का ध्वजारोहण करेंगे। यह दिन ऐतिहासिक इसलिए भी होगा कि इस दिन राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने की घोषणा भी की जाएगी। राम मंदिर के ध्वजारोहण के साथ प्रधानमंत्री पूरे विश्व को राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने का संदेश देंगे। ध्वज का स्वरूप कैसा होगा, रंग कैसा और प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा, इसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पांच अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य महल में विराजमान हुए थे। प्रधानमंत्री मुख्य यजमान थे।

शर्मनाक और नैतिक रूप से निंदनीय, पीएम मोदी ने इसाइली पीएम की तारीफ की तो हमलावर हुई कांग्रेस

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेस्ट एशिया शांति योजना के पहले चरण का समर्थन करने और इसाइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इस बयान को शर्मनाक और नैतिक रूप से निंदनीय बताया है। मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा को लेकर हुए नए समझौते का स्वागत किया और ट्रंप की सराहना की, जो हैरानी की बात नहीं है। लेकिन नेतन्याहू की बिना शर्त तारीफ करना शर्मनाक और नैतिक रूप से निंदनीय है, जिन्होंने पिछले बीस महीनों से गाजा में नरसंहार मचाया है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने फलस्तीन के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के भविष्य पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जिसे भारत ने नवंबर 1988 में ही मान्यता दे दी थी और जिसे अब 150 से अधिक देश मान्यता दे चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्ट बैंक में इसाइली बस्तियों के लगातार विस्तार पर भी कुछ नहीं कहा। बता दें कि ये पूरा मामला चर्चा का विषय तब बना जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक पोस्ट में लिखा था कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। यह इसाइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मजबूत नेतृत्व क्षमता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मिल रही मानवीय सहायता से उन्हें राहत मिलेगी और इससे स्थायी शांति की दिशा में रास्ता खुलेगा। ध्यान रहे कि यह समझौता इसराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति माना जा रहा है, जिसके तहत लड़ाई रोकने और कुछ बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है।

पीके की जन सुराज ने उतारे दिग्गज, गणितज्ञ-सिंगर समेत 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी!

पटना। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पटना की कुम्हरार सीट से प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा को मैदान में उतारा है। वहीं, करगहर सीट जहां से प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा थी वहां से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को उतारा गया है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 नवंबर और 11 नवंबर, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। राज्य का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर बना हुआ है, क्योंकि बदलते गठबंधन और आंतरिक कलह दोनों प्रमुख गठबंधनों को आकार दे रहे हैं। वर्तमान में, एनडीए के पास 131 सीटें हैं - जिसमें भाजपा (80), जेडी(यू) (45), हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (4) और दो निर्दलीय शामिल हैं। विपक्षी महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं - राजद (77), कांग्रेस (19), सीपीआई(एमएल) (11), सीपीआई(एम) (2) और सीपीआई (2)। इस साल के बिहार चुनावों में एनडीए, इंडिया ब्लॉक और प्रशांत किशोर को नई उभरती जन सुराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ??है कि जन सुराज चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक गठबंधन मतदाताओं से ऊब चुके हैं।

मायावती को उत्पीड़कों की आभारी बता अखिलेश का तीखा पलटवार, बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गुप्त समझौता किया है और कहा कि मायावती आपसी लाभ के लिए उत्पीड़कों की आभारी हैं। उनकी यह टिप्पणी मायावती द्वारा समाजवादी पार्टी को दोमुँहा कहने के बाद आई है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि क्योंकि उनकी अंदरूनी मिलीभगत जारी है, इसलिए वे अपने उत्पीड़कों के आभारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सपा और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने ही कांशीराम को इटावा से सांसद बनने में मदद की थी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर मायावती के अलावा किसी और ने उनकी मूर्ति लगवाई है, तो वह मैं हूँ... सपा सरकार के दौरान सभी स्मारकों का उचित रखरखाव किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) को भी दोहराया और इसे मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि सपा को राय में लोकतांत्रिक सरकार बनाने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखना

लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि क्योंकि उनकी अंदरूनी मिलीभगत जारी है, इसलिए वे अपने उत्पीड़कों के आभारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सपा और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने ही कांशीराम को इटावा से सांसद बनने में मदद की थी।

होगा। उन्होंने कहा, अगर हम लोगों से जुड़ते रहेंगे, तो निकट भविष्य में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। इससे पहले दिन में, मायावती ने समाजवादी पार्टी को दोगली करार देते हुए कहा कि यादव की पार्टी दलितों को तभी याद करती है जब उसे उनकी जरूरत होती है। बसपा संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक रैली में बोलते हुए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यादव की पार्टी पर राय में सत्ता में रहते हुए दलित स्मारकों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने उनके रखरखाव पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा, जब वे सत्ता में होते हैं, तो उन्हें न तो पीडीए याद आता है, न ही उससे जुड़े संतों, गुरुओं और महापुरुषों की। लेकिन जैसे ही वे सत्ता खो देते हैं, उन्हें अचानक हमारे संत, गुरु और महापुरुष याद आने लगते हैं। लोगों को ऐसे दोगले लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सराहना की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने उन पार्कों और अन्य स्मारकों का रखरखाव किया है जो बसपा के शासनकाल में बनाए गए थे। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि आगंतुकों से ली गई टिकट की राशि का उपयोग रखरखाव के लिए किया जाए। भाजपा सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि यह धन कहीं और नहीं लगाया जाएगा, बल्कि केवल रखरखाव के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके लिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है।